Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, on behalf of Shri Narender Singh Tomar, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 "

The motion was adopted.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, I introduce the Bill.

HON. SPEAKER: Hon. Members, there will be no 'Zero Hour' just now. शाम को जीरो ऑवर ले लेंगे।

Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally handover the text of the matter on the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received in stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

*t12

Title: Need to set up desalination plants in coastal areas of Maharashtra.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय सदन भली-भाँति जानता है कि मेरा गृह राज्य महाराट्र विगत कई सालों से सूखे की समस्या को झेल रहा है। सिंचाई से लेकर पेयजल की समस्या प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है। खेतों को पानी नहीं मिलना, पशुओं को पानी नहीं मिलना, लोगों को पेयजल नहीं मिलने से पूरे महाराट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। किसान के खेतों में फसल पानी के अभाव में सूखने से किसान बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी नहीं कर पाने से महाराट्र के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित भातसा डैम,वैतरणा डैम, एवं ताणसा डैम हैं, जिनका पानी पूरे मुंबई को जा रहा है। अगर महाराट्र के समुद्री तटों पर समुद्री पानी को पेयजल में परिवर्तित करने के आधुनिक प्लांट लगाए जाए, तो उपरोक्त डैमों का पानी उत्तर महाराट्र के लिए प्रयोग किया सकता है। इससे उत्तरी महाराट्र में सूखे से परेशान किसानों एवं नागरिकों को कुछ राहत दी जा सकती है। इसके लिए प. बंगाल एवं तमिलनाडु के समुद्र तटों पर समुद्री पानी को पेयजल में बदलने के कई प्लांट सफल रूप से चल रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। जैसा कि सदन जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफी प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने कार्यवाही भी की थी, परंतु अभी तक महाराट्र में इस समुद्री पानी से पेयजल बनाने हेतु किसी भी समुद्री तट पर डिसेलिनेशन प्लांट की घोाणा अभी तक नहीं की गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान समय में महाराट्र में सूखे की समस्याओं के तात्कालिक हल के लिए महाराट्र के समुद्री तटों पर डिसेलिनेशन प्लांट स्थापित किए जाएं, जिससे मुंबई को पानी की आपूर्ति की जा सके और भातसा डैम, वैतरणा डैम ए वं वैतरणा डैम से जो पानी मुंबई के लिए जाता है, उस पानी को उत्तरी महाराट्र के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में दिया जा सके।